की खेती को लोकप्रिय बनाने और उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के प्रचार में राज्य सरकारों के प्रयासों में उनकी मदद के लिए गेहूं, मक्का और कदन्नों के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, समेकित चावल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परि योजना, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम आदि जैसे विशेष फसल प्रधान कार्यक्रम जारी रखे जायेंगे । वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लि एक राष्ट्रिय पनधारा विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ।

अवैध भट्ठियों द्वारा इस्पात का उत्पादन

22. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1991 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "20 परसेन्ट स्टील प्रोडयूस्ड बाई इल्लीसिट फर्नेसिज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र में इस्पात-उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए निकट भविष्य में कोई कदम उठाने जा रही है, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री (श्री स तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रिपोर्ट की प्रमुख बातों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) गौण इस्पात क्षेत्र में इस्पात विनिर्माण की लाइसेंसीकृत इकाइयों को आधुनिक बनाने तथा उनकी क्षमता 2.5 लाख मी० टन वार्षिक तक बढ़ाने की अनुमति दी गयी है। इस क्षेत्र में और अधिक क्षमता की कुछ नई इकाइयों को स्थापित करने के लिए अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है।

विवरण

मृदु इस्पात और कच्चे लोहे की मदवार तथा आकारवार वीर्घावधि मांग की बाबत एन० सी० ए० ई० आर की रिपोर्ट की प्रमुख बातों को दर्शाने वाला विवरण

लोहे तथा इस्पात के विभिन्न उत्पादों की अनुमानित मांग :

1. तैयार मृदु इस्पात की अनुमानित मांग, जी.डी.पी. में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की परिकल्पना के संदर्भ में, वर्ष 1994–95 तक 214 लाख मी. टन और वर्ष 1999–2000 तक 292 लाख मी. टन होने की संभावना है। अनुमान है कि कच्चे लोहे की मांग वर्ष 1994–95 तक 20 लाख टन मी. तथा वर्ष 1999–2000 तक 25 लाख मी. टन तक हो जाएगी। वर्ष 2000 तक तैयार मृदु इस्पात की मांग में 6.04 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है।

2. इस्पात की चपटी मदों की मांग में 8.45 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है जबकि अचपटी मदों की मांग में 4.53 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है।

3. चपटे उत्पादों की दो मदों, शीत वेल्लित कायलों/चादरों और तप्त वेल्लित कायलों/चादरों की मांग में 9.35 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि होने की संभावना है जो सभी इस्पात मदों में सर्वाधिक है।

इस्पात की पुनर्वेलन इकाईयों की महत्वपूर्ण बातें

1. भारत में 1093 पुनर्वेलन इकाइयां हैं जिनकी कुल स्थापित वार्षिक क्षमता 210 लाख मी. टन है. जिसमें 7,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया गया है और 79,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया है।

2. पुनर्वेलन उद्योग 74 लाख मी. टन कच्ची सामग्री की खपत करते हैं और 66 लाख मी. टन तैयार इस्पात का उत्पादन करते हैं। आदान-उत्पादन का अनुपात 1:0.9 है।

3. सेल/टिस्को/इस्को आदि के लिए पुनर्वेलन इकाइयों द्वारा 8.6 लाख मी. टन तैयार इस्पात का उत्पादन किया गया है जो कुल उत्पादन का लगभग 13 प्रतिशत है।

4. प्रेरण भट्ठी इकाइयों के कच्चे माल के आदान में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

5. सरकार और इसकी एजेंसियों, व्यापारियों और अन्यों के लिए तैयार माल की बिक्री क्रमशः 10.1% 81.3% और 0.6% है।

6. 15.17 प्रतिशत इकाइयां नई इकाइयां शामिल करना चाहती हैं।

32.50 प्रतिशत इकाइयां विस्तार करने की इच्छुक हैं।

18.39 प्रतिशत इकाइयां विविधीकरण करना चाहती हैं।

13.50 प्रतिशत इकाइयां प्रतिस्थापित (कुछ) करना चाहती हैं, और

15.39 प्रतिशत इकाइयां विस्तार के विभिन्न चरणों में हैं।

7. तैयार वस्तुओं की 90 प्रतिशत बिक्री उसी राज्य में होती है जहां उसका उत्पादन होता है।

8. कच्चे माल और तैयार इस्पात की 90 प्रतिशत ढुलाई सड़क मार्ग से होता है।

New Railway Lines/Trains for Gujarat

23. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: SHRI SOM PAL:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any new Railway line is going to be laid in Gujarat;

(b) what are the new trains going to be started from *now* onwards;

(c) whether Veraval-Rajkot broad gauge conversion is going to be undertaken; if so, by when; what are the major aspects of the project report of this railway; and

(d) whether Government would convert the line soon if the necessary finance is made locally available?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI M. MALLIKARJUN): (a) The work on the following projects in Gujarat has already been started:—

(i) Godhra-Dahod-Indore (100 km in Gujarat)

(ii) Kapadvanj-Modasa (60 km)

(iii) Viramgam-Bhildi (40 km new line 117 km conversion)

(b) The following additiona services have been introduced to serve the State of Gujarat w.e.f 1-7-1991:

. (i) Ahmedabad-Bombay Centra Karnavali Express.

(ii) Wansjaliya-Porbandar Shut the

(c) and (d) Western Railway ha been asked to study the possibl alternatives and submit a Surve Report in this regard.